SOME HON. MEMBERS: We can continue it tomorrow, Sir. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA : But you can take up Special Mentions, now.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay. Tiwari*ji*, you can continue your speech tomorrow. Now, Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS *(Contd.)*

Demand to include Bhojpuri in Eighth Schedule of the Constitution

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे विशेष उल्लेख का विषय है - भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना।

उपसभाध्यक्ष महोदय, देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भोजपुरी बोली जाती है। देश के कोने-कोने में भोजपुरी भाषी लोग निवास करते हैं। देश के बाहर कई देशों जैसे मारीशस, टोबैगो, ट्रिनीडाड आदि में भोजपुरी वहां के सरकारी काम काज की भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। यह आश्चर्च और खेदजनक है कि जहां एक ओर देश के एक सीमित भूक्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में काफी पहले शामिल की जा चुकी हैं तथा सरकार उनके संवर्द्धन और विकास के लिए प्रोत्साहन दे रही है, वहीं दूसरी ओर भोजपुरी, जो करोड़ों लोगों की मातृभाषा है, उसे अभी तक आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। जहां भोजपुरी का जन्म हुआ, वहीं भोजपुरी सर्वाधिक उपेक्षा की शिकार हो, यह भोजपुरी भाषी लोगों के साथ नाइंसाफी है, जिसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि भोजपुरी भाषी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

Demand to revamp the National Saving Scheme to strengthen the economy of the country

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): The need to revamp the National Saving Scheme of the country, in this period of economic recession, is highly necessary to promote the savings in our country and provide facilities for the State to strengthen the social welfare scheme. The interest rate of the National Saving Scheme is drastically diminishing. For the past several years, there has been no increase at all. On the other hand, the commercial banks and other financial institutions are offering higher rates of interest for attracting depositors. Hence, there is a huge withdrawal of the national deposits under the NSS. If similar scenario prevails for some more time, the future of the NSS will be in danger. As the scheme itself is losing importance, the SAS and the MPKBY agents, who are earning their livelihood out of the nominal commission from this scheme, are also very badly affected.

Hence, I would like to request the hon. Finance Minister to take urgent steps to rejuvenate the NSS and strengthen our national economy.

Concern over Frauds in issuing of Caste Certificates

श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष जी, मेरे विशेष उल्लेख का विषय है- जाति प्रमाण पत्रों का फर्जी वाड़ा।